औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना (आई॰आई॰यू॰एस॰) के अंतर्गत चंदेरी का विकास

*302. श्रीमती माया सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत चंदेरी हेतु 887.50 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि परियोजना प्रस्ताव, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई॰आई॰यू॰एस॰) के मानदण्डों के अनुरूप नहीं था, अत: मध्य प्रदेश सरकार को उस परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी गई थी। संशोधित प्रस्ताव 8 दिसंबर, 2006 को प्राप्त हुआ है। आई॰आई॰यू॰एस॰ के लिए 10वीं योजना का संपूर्ण आबंटन पहले ही स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में तय किया जा चुका है इसलिए किसी नए प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

Development of Chanderi under IIUS

†*302. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal for Chanderi under the Industrial Infrastructure Upgradation Scheme involving Rs. 887.50 lakh, has been received from the Government of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the present status of the proposal and by when it would be approved?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ASHWANI KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) Since the project proposal did not conform to the Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (IIUS) parameters, the Government of Madhya Pradesh was advised to revise the project proposal. The revised

†Original notice of the question was received in Hindi.

proposal has been received on 8th December 2006. As the entire Tenth Plan allocation for the IIUS has already been committed for the sanctioned projects, no new proposal is being sanctioned.

श्रीमती माया सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है, उसके मुताबिक यूपीए सरकार की इच्छा है कि हथकरघा या इस तरह के हुनर वाले जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मदद करने की नीति है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। चंदेरी के चौबीस घंटे में से अठारह घंटे लूम पर बैठकर काम करने वाले लोगों की मदद के लिए जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को आपने टेक्नोकेलिटी के आधार पर कैंसिल किया है। इसके लिए आप पार्शियल ग्रांट दे सकते थे। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने प्रतिशत स्वीकार किए गए हैं? कृपया मुझे वर्षवार 2005-06 की स्थिति बताएं।

श्री अश्विनी कुमार: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि 2005 में चंदेरी के लिए एक प्रस्ताव आया था, जिसके लिए 5,57,00,000 की राशि [illegible] थी। वह प्रस्ताव नीति के आधार पर पूरा नहीं उतरता था, इसलिए रिवाइज प्रपोजल मांगा गया, जो दिसम्बर 2006 में आया है। इसके लिए 19,00,00,000 की राशि मांगी गई है। माननीय, आज की स्थिति यह है कि 670 करोड़ की राशि जो इस स्कीम के लिए उपलब्ध थी, वह पूरी तरह से वितरित हो चुकी है। हमने प्लानिंग कमीशन से दरख्वास्त की है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि राशि को बढ़ाया जाएगा और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसकी स्कीम चलेगी। उस समय चंदेरी का जो प्रपोजल आया है, उसे जरूर नियमानुसार कंसीडर किया जाएगा। जहां तक बुनकरों का सवाल है, हमारी सरकार की उनके प्रति पूरी वचनबद्धता है। यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ या उनके किसी प्रस्ताव के साथ किसी किस्म का भेदभाव हो। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि अब तक के स्वीकृत बजट में राज्यों को कितनी धनराशि उद्योग संवर्धन की सहायता के रूप में एलाट करने का सरकार का विचार है?

श्री अश्विनी कुमार: 670 करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान है, 470 करोड़ रुपए के लगभग डिसबर्समेंट हो चुकी है, 26 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हो गए हैं, 46 प्रोजेक्ट्स pending हैं और 47 प्रोजेक्ट्स रिजैक्ट हो चुके हैं।

MS. MABEL REBELLO: Sir, Chanderi is a place known for traditional art of weaving. Very fine and beautiful *sarees* are woven there. But the craftsmen are dying there today because they are not able to get you

know, the absolute white type of yarn, and are also not able to market their product. I would like to know from the hon. Minister how he is going to save this art from being dead and how he is trying to save the art of craftsmen.

श्री सभापति: आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं?

सुश्री मेबल रिबैलो: गुस्से में क्या सर, मैं आपसे पूछ रही हूं ...(**व्यवधान**)... ये craftsmen dead हो जाएंगे। They will be dead in the times to come. And the art also is a perishable art. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है ...(**व्यवधान**)...

MS. MABEL REBELLO: They are not encouraging the small people to learn this craft...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है ...(**व्यवधान**)...

MS. MABEL REBELLO: ...and it is not possible for anybody to pick it up.

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, मंत्री महोदय, इनको शांत करिए।

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I fully appreciate the concern of the hon. Member. I have stated unambiguously that our Government is committed, in every possible way, to the welfare of the artisans, and we will continue. ...(*Interruptions*)...

सुश्री मेबल रिबैलो: क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ...(**व्यवधान**)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I have said for the benefit of the hon. Member that this Government stands totally committed to the welfare of the artisans, and we will do everything possible to ensure their well-being.

सुश्री मेबल रिबैलो: सर, यह जनरल हो गया है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्रीमती नजमा हेपतुल्ला।

सुश्री मेबल रिबैलो: मैंने particularly चन्देरी के लिए पूछा था ...(**व्यवधान**)... इनको चन्देरी के लिए कहना चाहिए था ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए, हो गया।

सुश्री मेबल रिबैलो: सर, इन्होंने general answer दे दिया है सबके लिए ...(व्यवधान)... इससे क्या मतलब ...(व्यवधान)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Including Chanderi. ...(*Interruptions*)... Including for the artisans of Chanderi ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat.

सुश्री मेबल रिबैलो: चन्देरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, वह बताएं ...(व्यवधान)... No steps are taken to save the art. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ये अभी कुछ दे देते, लेकिन आप गुस्से में बोल रही हैं, इसलिए नहीं दिया ...(व्यवधान)...

सुश्री मेबल रिबैलो: सर, आपको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, आप प्रोटेक्शन ही नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: चलिए, चलिए। प्रोटेक्शन दे रहा हूं न, एक महिला इधर से, एक महिला उधर से...

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: सभापति जी, माया जी ने यह बात ठीक कही कि खाली टैक्नीक्लिटीज की वजह से आपने उनकी ग्रांट नहीं दी। आपने अगर उनको रिवाइज करने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा होता, तो आप इंतज़ार भी कर सकते थे कि जब revised scheme आएगी, तब देंगे। अगर sincerity हो, आपकी नीयत में कोई खोट न हो, तो आप ऐसा करते। प्रश्न 303 में भी जो सवाल उड़ीसा के बारे में पूछा गया है, यह सवाल मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सबके ऊपर लागू होता है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, वह नहीं है।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: यह सवाल इन सबके ऊपर लागू होता है कि जितने भी हैंडलूम वर्कर्स हैं, वे खुदकुशी कर रहे हैं और आप इतना छोटा सा amount release करने के लिए इतनी अड़चनें लगा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि आपकी नीति इस बारे में सही है या नहीं?

श्री सभापति: ठीक है। नीति और नीयत।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: सर, नीयत के ऊपर तो मुझे बहुत ही शक है।

श्री अश्विनी कुमार: सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी नीयत भी सही है और नीति भी सही है और जहां तक बुनकरों के प्रति हमारी वचनबद्धता का सवाल है, यह जगज़ाहिर है और मैं एक आश्वासन और देना चाहूंगा कि जहां तक चन्देरी का सवाल है, अगर प्लानिंग कमीशन द्वारा इसके लिए और राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो इस प्रोजेक्ट को नियमानुसार consider किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Next Question 303.

श्री मोतिउर रहमान: सर, प्रश्न 316 भी इसी तरह का है, इन दोनों को मिला दिया जाए।

श्री सभापति: अभी एक का जवाब आने दीजिए, मैं देख लेता हूं।

Integrated Handloom Cluster Development Programme

*303. MS. PRAMILA BOHIDAR:†
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that handloom sector is the largest source of employment in rural areas, after agriculture;

(b) whether Government have launched the Integrated Handloom Cluster Development Programme for development of this sector;

(c) if so, whether it is a centrally funded project; and

(d) if so, the details of clusters being developed in Orissa and the amount of Central aid since provided to these centres?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Integrated Handloom Cluster Development Programme

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of India has launched "Integrated Handloom Cluster Development Scheme (IHCDS)" in the year 2005-06 which is 100% Central Sector Scheme.

(d) Two clusters i.e. Sonepur and Bargarh in Orissa have been approved for their integrated and holistic development and a sum of Rs. 21.05 lakh for each cluster has been released so far to the implementing agencies.

MS. PRAMILA BOHIDAR: Hon. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister what are the basic infrastructures being provided or proposed to be provided in the Integrated Handloom Cluster Development Programme? Are banking finance and marketing facilities being provided to weavers in these clusters? If so, what are the details, State-wise?

†[The question was actually asked on the floor of the House by Ms. Pramila Bohidar.]